Website:- www.dipronline.org
email:- projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

गर्मी के मौसम में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति पर सत्त निगरानी रखी जाये - उपाध्याय

झुंझुनू, 5 मार्च: उद्योग विभाग के आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव राजहंस उपाध्याय ने अधिकारियों से कहा है कि वे पेयजल आपूर्ति को बिना किसी व्यवधान के आपूर्ति करने के लिए निरन्तर निगरानी रखें और जहां कहीं भी पेयजल से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती हो, उसका अविलम्ब निराकरण किया जाये। उन्होंने विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से भी कहा है कि वे गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति के लिए विद्युत आपूर्ति को चुस्त-दुरूस्त रखें ताकि लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। वे शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा भवन में पेयजल, विद्युत, मौसमी बीमारियों एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें और नीचले स्तर के अधिकारियों को भी सावचेत किया जाये कि इन व्यवस्थाओं में ढिलाई बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं के संचालन में अगर किसी प्रकार के जरूरी सामान की आवश्यकता हो तो उसकी उपलब्धता उच्च अधिकारियों से अविलम्ब कराई जाये। उन्होंने कहा कि जिले की कन्टीजेन्सी योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। विभागीय अधिकारी इस बात का विशेष प्रयास करें कि सभी स्वीकृत कार्य मार्च तक आवश्यक रूप से पूर्ण करवा लिये जायें। उन्होंने जिले में मौसमी बीमारियों के साथ-साथ अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी की।

जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने विश्वास दिलाया कि गर्मी के मौसम में विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति को बिना किसी विघ्न के संचालित करवाने के पूरे प्रयास किये जाएंगे और स्वीकृत कार्यों को भी हर संभव मार्च तक पूरा कराने के लिए अधिकारियों को ताकीद किया जायेगा। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने भी अधिकारियों को विद्युत और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला सहित विद्युत, जलदाय, पशुपालन, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

बैंकर्स सरकारी योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें

-कलेक्टर

613.13 करोड़ रूपये की वार्षिक साख योजना का अनुमोदन

झुंझुनू, 5 मार्च: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने बैंकर्स से कहा है कि वे सरकारी योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्य अगले 10 दिन में अर्जित करें, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को हर हाल में मिलना चाहिए। बैंक ऋण देने में अनावश्यक रूप से टाल-मटोल नहीं करे और आवेदक को बिना किसी कारण के चक्कर कटवाने के साथ ऋण वितरण में देरी भी नहीं करें। वे शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा भवन में जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि बैंक ऋण देने में बहाने बाजी नहीं करें। जो बैंक इस साल के आवंटित लक्ष्य 15 मार्च तक अर्जित नहीं करेंगे उनके यहां से सरकारी योजनाओं के खाते लक्ष्य अर्जित करने वाले अन्य बैंकों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो बैंकर्स लक्ष्य को अर्जित करने में बिना किसी कारण के आनाकानी कर रहे हैं, उनके विरूद्ध उच्च अधिकारियों व आर.बी.आई. को भी लिखा जायेगा। बैठक में जिले की नाबार्ड द्वारा तैयार की गई 2010-11 की वार्षिक साख योजना 613.13 करोड़ रूपये का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बताया गया कि वार्षिक साख योजना में से कृषि क्षेत्र के लिए 497.44 करोड़ रूपये व एस.एम.ई. के लिए 23.30 करोड़ रूपये तथा प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 92.39 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

जिला कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित नहीं वाले बैंकर्स और कम प्रगति वाले बैंकर्स के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमें भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को देना ही है तो यह वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही क्यों ना कर दिया जाये। बिना किसी कारण के आवेदकों को एक साल तक लटकाये रखना मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स को चाहिए कि वे अग्रमी रेशो बढ़ायें और समय पर एल.बी.आर. भी भिजवायें और एक व्यक्ति के डिफाल्टर होने पर अन्य आवेदकों को ऋण वितरण किया जाना नहीं रोका जाये। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकर्स का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है यह चिन्तनीय विषय है। उन्होंने कहा कि गत बार सभी ने वायदा किया था कि योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पहले अर्जित कर लिया जायेगा, लेकिन अभी तक भी 50 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित नहीं हो पाये हैं।

रिजर्व बैंक के अग्रणी बैंक अधिकारी आर.पी. पालीवाल ने सभी बैंकर्स से कहा कि जिले में अग्रिम जमा अनुपात बहुत कम है इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी बैंकर्स अग्रिम बढ़ाने के कार्य को गंभीरता से लेवें और कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण देने में बिना किसी कारण के विलम्ब भी

नहीं करें। उन्होंने कहा कि जिले के 185 गांवों में अभी भी बैंकिंग सुविधा नहीं है। इन गांवों को भी किसी न किसी तरह बैंक से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने ऋण स्वीकृति और ऋण वितरण के अनुपात में काफी अंतर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऋण आवेदन प्राप्ति के बाद उन्हें अविलम्ब स्वीकृत करके 15 दिन में ऋण वितरण किया जाना सभी बैंकर्स का दायित्व बनता है। बैंकर्स को चाहिए कि वे आवेदन पत्रों को ऋण रजिस्टर में दर्ज भी करें।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबन्धक सी.आर. मीणा ने भी अग्रिम जमा अनुपात बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि सभी बैंकर्स स्वीकृत ऋण आवेदकों को 15 मार्च से पहले ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। यह बैंक हित में होगा और आवेदक के हित में भी। उन्होंने निजी बैंकर्स से भी कहा कि वे भी सरकारी योजनाओं के लक्ष्य अर्जित करने में अपना सहयोग अदा करें। नाबार्ड के डी.डी.एम. अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि गत तीन साल से अग्रिम जमा अनुपात निरन्तर कम होता जा रहा है यह हम सबके लिए हित में नहीं है। हमें कृषि क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण को बढ़ाते हुए अग्रिम को भी बढ़ाना होगा।

अग्रणी जिला प्रबन्धक रघुवीर सिंह दुलड़ ने बताया कि जिले के विभिन्न बैंकों की कुल जमाएं 2156.78 करोड़ रूपये है, जबकि अग्रिम 997.71 करोड़ रूपये है तथा अग्रिम जमा अनुपात 46.26 प्रतिशत है। उन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, कृषि, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा वर्ष 2009-10 की वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों व उपलब्धि, राको एक्ट में ऋण वसूली, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह आदि पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम के परियोजना प्रबन्धक उत्तम सिंह, परियोजना अधिकारी सुशील कुमार, उद्योग विभाग के महाप्रबन्धक मनीराम व एस.जी.एस.वाई. के राजवीर सिंह ने विभागीय योजनाओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए लक्ष्यों को मार्च माह में अर्जित करने पर बल दिया। बैठक में सभी बैंकर्स प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।